संख्या:256/2022/880/35-4-2022/001-35-4/11/2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 11 अगस्त,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र-बिठूर में शासनादेश संख्या-285/2021/2126/35-4-2021, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 21 कार्यों कीरू. 244.57 लाख की लागत परप्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 209.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा पत्रांक: 516/त्व0आ0वि0यो0/वि0स0-बिठूर/2021-22, दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 21 कार्यों में से 04 कार्यों की कुल लागत रू0 90.47 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू0 60.00 लाख का पूर्ण व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत उक्त 04 कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 60.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष रू. 30.47 लाख (रूपये तीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	रतनपुर जयराम के घर से ओम प्रकाश के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	19.48	15.00	04.48
2	पाल्हेपुर में रामबाबू के दरवाजे से शिवरतन प्रजापति पाल्हेपुर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	25.91	15.00	10.91
3	भिसार में सुध शर्मा से राकेश तोमर की दुकान तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	18.96	15.00	03.96
4	कैन्धा में संजय साहू के घर से श्याम सिंह के घर तक होते हुए रमेश प्रजापति के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	26.12	15.00	11.12
	योग	**90.47**	**60.00**	**30.47**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्थाको उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,47,000 (रूपये तीस लाख सैतालीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या: 256/2022/880(1)/35-4-2022/001-35-4/11/2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।
11- गार्ड फाईल।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कानपुर नगर ।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in